Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 112 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बड़ा कदम

पंचायतों में अब नहीं चलेगी सरपंच पतियों की दखल

रायपुर, 16 मई (हाईवे चैनल)। पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया का स्वतंत्र और प्रभावी हिस्सा बनाना है।

जारी निर्देश के अनुसार, अब ग्राम पंचायत, जनपद एवं अन्य पंचायत बैठकों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी. किसी भी रिश्तेदार, प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति को उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. आवश्यकता पड़ने पर फेस रिकॉग्निशन और बायोमीट्रिक अटेंडेंस जैसी तकनीकों का उपयोग कर उपस्थिति सत्यापित की जाएगी। विभाग ने पंचायत बैठकों और ग्राम सभाओं की कार्रवाई को सभासार पोर्टल, निर्णय ऐप तथा अन्य अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका दर्ज हो सके। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल निगरानी से प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा. महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक और सामाजिक रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए जिले में जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

पंचायतों में प्रभावी कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों की सफलता की कहानियों को सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रचारित करने की भी योजना बनाई गई है, ताकि अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिल सके. पेसा क्षेत्र की पंचायतों में ग्राम सभा से पूर्व महिला सभा आयोजित करना अनिवार्य किया गया है, वहीं सामान्य क्षेत्रों में भी महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने के लिए महिला सभाओं के आयोजन के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. विभाग ने जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत पेटी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के लिए जवाबदेह बनाया गया है. प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्र और सक्रिय भागीदारी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लेने कहा है, साथ ही एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

भारत में 3 करोड़ बैरल तक तेल स्टोर करेगा यूएई, तेल और गैस की सप्लाई पर हुई महाडील

नई दिल्ली, 16 मई (न्यूज चैनल)। भारत-यूएई डील: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और लाल सागर के संकट के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर एक ऐसा मास्टरप्लान तैयार किया है, जो भविष्य में भारत की तेल की जरूरतों को सुरक्षित रखेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई के कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस नई व्यवस्था के तहत यूएई अब भारत में लगभग 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई हाईलेवल बैठक के बाद लिया गया। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस् लिमिटेड और अबुधाबी नेशनल ऑइल कंपनी के बीच एक नया रणनीतिक समझौता हुआ है। इसके जरिए भारत के तेल भंडारण नेटवर्क में यूएई की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में तेल आपूर्ति में किसी भी वैश्विक संकट के दौरान भारत को राहत मिलेगी। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिर स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। भारत और यूएई दोनों ने सुरक्षित समुद्री मार्ग और जहाजों को निर्बाध आवाजाही को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी बताया। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि international sea routes की सुरक्षा ऊर्जा व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने यूएई पर हुए हालिया हमलों की निंदा करते हुए उसके प्रति समर्थन भी जताया।

यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के महत्वपूर्ण विदेश दौरे के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने आर्थिक संबंधों को नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ सफल वार्ता करने के बाद नीदरलैंड पहुंचे। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर डच सरकार ने उनका पलक-पांवड़े बिछाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में रॉयल मिलिट्री परिवार के प्रमुख रियर एडमिरल लुडगर ब्कमेलार, डच विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन और नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

ब्रेकिंग न्यूज

रॉबर्ट वाड्रा को मिली जमानत, बोले- मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं

नई दिल्ली, 16 मई (न्यूज चैनल)। शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वे निडर हैं और कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं, बस ईडी को झेलना है। उन्होंने कहा कि झेलने की क्षमता है, वह सबसे बड़ी चीज है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि ईडी को सरकार चला रही है और ईडी सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा। मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें कोर्ट से 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।

संदिग्ध युवक से 21.30 लाख नगद बरामद, जांच में जुटी पुलिस

कांकेर, 16 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक युवक के कब्जे से 21 लाख 30 हजार रुपए नगद बरामद किए हैं। वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए रकम जब्त कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में कांकेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में नगदी लेकर संदिग्ध हालत में घूम रहा है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद मुस्ताक (36 वर्ष) निवासी संतोषी नगर टिकरापारा थाना क्षेत्र रायपुर बताया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद ग्रे-काले रंग के बैग से 500 रुपए के 42 बंडल और 100 रुपके के 3 बंडल बरामद हुए। गिनती में कुल 21 लाख 30 हजार रुपये नगद पाए गए।

चूहा- सुनती हो, अब सरपंच पतियों के ऊपर गिरेगी गाज। चुहिया- हां जी, पत्नी को चूल्हा चौका सौंपकर खुद नेतागिरी करने चले आते हैं..!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे, तीन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

रायपुर, 16 मई (हाईवे चैनल)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर और बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों, सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाह 17 मई की शाम रायपुर पहुंचेंगे और रात विश्राम करेंगे। वे 18 मई को रायपुर में डायल-112 इमरजेंसी सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और फिर जगदलपुर जाएंगे।

यहां 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा परिषद की बैठक में उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने वरिष्ठ अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपते हुए गंभीरता एवं समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। बस्तर विकास की नई गाथा लिखेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा, बस्तर में शांति स्थापना के बाद इस स्तर की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं को लेकर पूरी तरह संकल्पित है।

आदेश जारी: अरुण देव गौतम प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी

रायपुर, 16 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। गृह (पुलिस) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम अब तक प्रभारी डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए गठित पैनल की अनुशंसा के बाद राज्य शासन ने उन्हें नियमित रूप से डीजीपी पद पर पदस्थ किया है। अरुण देव गौतम को प्रशासनिक और पुलिसिंग अनुभव के लिहाज से प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों में गिना जाता है। किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले अरुण देव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अभयपुर गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 2 जुलाई 1967 को हुआ। वे पांच भाई और एक बहन हैं। उन्होंने आठवीं तक की स्कूली शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई के पास प्रयागराज आ गए। राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद से दसवीं और बारहवीं पूरी करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आर्ट्स लेकर बीए और फिर राजनीति शास्त्र में एमए किया।

इलाहाबाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान उनके कई दोस्तों ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। इसको देखते गौतम ने ठान लिया कि वे भी देश की सबसे बड़ी इस प्रतियोगी परीक्षा पास करेंगे। मन में संकल्प लेकर वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली दाखिला ले लिया। वहां से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके बाद पीएचडी करना प्रारंभ किया। यूपीएससी परीक्षा में पहली बार असफल रहने के बाद अरुण देव गौतम ने ध्येय की प्राप्ति के लिए पढ़ाई में सब कुछ झोंक दिया। और दूसरी बार मे आईपीएस सलेक्ट हो गए। अरुण देव गौतम यूपीएससी निकालकर 1992 बैच के आईपीएस बने। 12 अक्टूबर 1992 को उन्होंने आईपीएस की सर्विस ज्वाइन की। उन्हें पहले मध्यप्रदेश कैडर एलॉट हुआ था। प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर उनकी जबलपुर में पोस्टिंग हुई।

महिला अधिवक्ता की हत्या, वकीलों ने किया प्रदर्शन, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग

रायगढ़, 16 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला अधिवक्ता आराधना सिदार की हत्या के मामले को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। आज वकीलों ने जिला न्यायालय परिसर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जुलूस निकालकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। गौरतलब है कि करीब चार दिन पहले पुंजीपथरा थाना क्षेत्र के ग्राम तुमीडीह में महिला की अर्धनग्न लाश बरामद हुई थी। शव की हालत देखी थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जिसके चलते पुलिस लगातार शिनाख्त का प्रयास कर रही थी। बुधवार को मृतका की बहन ने कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर शव की पहचान अपनी बहन अधिवक्ता आराधना सिदार के रूप में की।

नक्सल मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज, 182 दिन देरी, माफी भी अस्वीकार

बिलासपुर, 16 मई (हाईवे चैनल)। नारायणपुर के चर्चित नक्सल प्रकरण में आरोपियों को मिली डिफॉल्ट बेल को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकारी प्रक्रियाओं और फाइलों के लंबित रहने का हवाला देकर देरी माफ नहीं की जा सकती. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने 182 दिन की देरी को अस्पष्टीकृत और लापरवाहीपूर्ण मानते हुए अपील को समयसीमा से बाधित बताते हुए खारिज कर दिया। दरअसल, मामला नारायणपुर जिले के ओरछा थाना में दर्ज अपराध से जुड़ा है. इस केस में चंपा कर्मा, मांगो मंडावी, संकू मंडावी और लच्छू मंडावी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. विशेष न्यायाधीश, एनआईए एक्ट एवं अनुसूचित अपराध न्यायालय, नारायणपुर ने 11 सितंबर 2025 और 24 सितंबर 2025 को आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दे दी थी. राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन यह अपील निर्धारित समयसीमा से 182 दिन की देरी से दायर हुई।

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रस्ताव आने, शासन की मंजूरी मिलने, दस्तावेज जुटाने और फाइल प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा. उन्होंने कहा कि शासन एक बहुस्तरीय व्यवस्था है, जहां विभागीय औपचारिकताओं के कारण विलंब हो गया।

सुशासन तिहारः सीएम साय पहुंचे कोसला गांव, ग्रामीणों ने किया स्वागत

जांजगीर-चांपा, 16 मई (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तहत का औचक निरीक्षण में अचानक जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोसला पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर जैसे ही ग्राम कोसला में उतरा वैसे ही प्रशासनिक अमले में हलचल मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए सुशासन तिहार 2026 मनाया जा रहा है। यह अभियान 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तहत का औचक निरीक्षण में निकले।

सुहागिन महिलाओं में दिखा वट सावित्री व्रत का उत्साह

बरगद वृक्ष की पूजा कर मांगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

रायपुर, 16 मई (हाईवे चैनल)। ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर रायपुर शहर में वट सावित्री व्रत को लेकर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही शहर के मंदिरों और वट वृक्षों के पास सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां महिलाओं ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने बरगद वृक्ष की परिक्रमा करते हुए व्रत कथा सुनी और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। पूरे शहर में धार्मिक और भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पूजा के दौरान महिलाओं ने व्रत कथा सुनी और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए पूजा संपन्न की। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना का आयोजन भी किया गया, जहां महिलाओं ने भक्ति गीत और पारंपरिक लोकगीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। सुबह से ही पूजा स्थलों पर चहल-पहल बनी रही और पूरे शहर में धार्मिक आस्था का माहौल देखने को मिला। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इस अवसर पर पारंपरिक संस्कृति, धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कारों का सुंदर संगम देखने को मिला।

खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा नाकेबंदी में 14 हाईवा जब्त किया

रायपुर/आरंग, 16 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी का सीना चीरकर अवैध कमाई में जुटे रेत माफियाओं के खिलाफ रायपुर खनिज विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है. रायपुर कलेक्टर के सख्त आदेश और खनिज प्रशासन के उप संचालक राजेश मालवे के कड़े तेवरों के बाद विभाग ने आरंग-खरोरा मुख्य मार्ग पर ग्राम रानीसागर में आधी रात को बड़ी नाकेबंदी की. इस हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन में अवैध रेत से लदे 14 भारी-भरकम हाइवा वाहनों की जब्ती की गई. इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, खनिज विभाग को पिछले कुछ समय से रेत क्षेत्र से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर रेत तस्करी के लगातार इनपुट्स मिल रहे थे. सूचना की तस्दीक होते ही खनिज निरीक्षकों की टीम ने ग्राम रानीसागर के पास नाकेबंदी की. जैसे ही रेत से भरे हाइवा वाहनों का काफिला वहां से गुजरा, टीम ने उन्हें रोक लिया. जब चालकों से वैध दस्तावेज, रॉयल्टी रसीद और पीटपास (परिवहन पास) की मांग की गई, तो वे सकपका गए. बिना किसी वैध कागजात के शासकीय संपदा की चोरी कर जा रहे इन सभी 14 हाइवा वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया गया।